



उदयपुर की लाइफ लाइन फतहसागर झील के इतिहास में पहली बार नवम्बर के महीने में चादर चली है। मावठ की बारिश के कारण झील छलक उठी है। पानी की आवक को देखते हुए बुधवार को सुबह इसके गेट खोले गए। छलकती हुई झील को देखने बड़ी तादाद में लोग फतहसागर पहुंचे।

नवम्बर में पहली बार फतहसागर झील पर चादर चली, चारों गेट खोले

इस साल डेढ़ माह के अंतराल में दूसरी बार फतहसागर छलका

उदयपुर, 24 नवम्बर (कास)। लेकसिटी की लाइफलाइन मानी जाने वाली फतहसागर झील में पहली बार नवम्बर माह में चादर चली है। पहले गत 7 अक्टूबर को करीब 48 दिन पहले इस पर चादर चली और मावठ की बारिश से बुधवार सुबह इसमें हुई पानी की आवक को देखते हुए इसके गेट पुनः खोले गए। जिला कलेक्टर व संचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इसके चारों गेट एक-एक इंच खोले गए हैं। प्रतिदिन रात 9 बजे इसके गेट पुनः बंद कर दिए जाएंगे और रात भर में 13 फीट 4 इंच से ऊपर जलराशि की मात्रा को देखते हुए इसके गेट खोले जाएंगे।

जिला कलेक्टर चेतन देवडा ने बुधवार को फतहसागर झील के गेट खुलवाए। बुधवार सुबह 9:15 बजे

- सुबह 9.30 बजे जिला कलेक्टर की मौजूदगी में चारों गेट एक-एक इंच खोले गए।
- फतहसागर के छलकने से पर्यटन को मिली बूस्टर डोज।

एक-एक कर जैसे ही फतहसागर के चारों गेट खुले तो हर कोई इस नजारे को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद करता नजर आया। कलेक्टर देवडा ने इस अवसर पर कहा कि "मैं बहुत किस्मतवाला हूँ कि मुझे अपने कार्यकाल के डेढ़ साल में तीसरी बार फतहसागर के गेट खोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए, उदयपुरवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है।

उन्होंने कहा कि उदयपुर अपनी झीलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यह पर्यटन नगरी है। जब

फतहसागर भरता है तो उदयपुरवासियों में एक नई ऊर्जा, खुशी का संचार होता है। यह झील जब भरती है, तो उदयपुरवासियों की खुशियां परवान पर होती हैं। जिला कलेक्टर ने इससे पूर्व विधि विधान के साथ इससे पहले फतहसागर की पूजा-अर्चना की। इस दौरान राजसमंद जिला कलेक्टर अरविन्द पोसवाल, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, जल संसाधन विभाग से भुवन भास्कर-अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ऋषभ कुमार जैन-अधीक्षण अभियंता, कैलाश जैन-

अधिशासी अभियंता, जीवनराम मीणा- सहायक अभियंता एवं जगदीश डांगी-कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। करीनाकाल के बाद दीवाली के दौरान भी रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक उदयपुर आए थे। अब लेकसिटी सर्दियों की छुट्टियों और नए साल के जलक्रीड़ा और आनंदन के लिए, उन्होंने ममता के साथ मीटिंग की थी। तृणमूल के टिवट हंडल ने भी ममता के साथ उनकी मीटिंग की पुष्टि कर दी है। उनके उक्त सहायक ने कहा कि यद्यपि डॉ. स्वामी औपचारिक रूप से तृणमूल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वे ममता के पक्ष में तो जा ही चुके हैं। दरअसल, वे अपने राज्यसभा के कार्यकाल के बीच में अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी राज्यसभा सीट के बीच में अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी राज्यसभा सीट को खोना नहीं चाहते। वे

जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की एक और छात्रा कोरोना संक्रमित मिली

स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और मौजूदा हालात को लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तैयार की

- इस रिपोर्ट पर सरकार के स्तर पर फैसला किया जाएगा।
- शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में शिक्षा व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की चर्चा की।
- प्रदेश में बुधवार को थोड़ी गिरावट के बाद 14 नए संक्रमित मिले हैं।

इंटरनेशनल स्कूल की एक और छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है। फिलहाल उसका इलाज बोर्डिंग सेंटर में ही चल रहा है। इस बीच राज्य में थोड़ी गिरावट के बाद 14 नए रोगी मिले हैं, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 141 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 87 मामले जयपुर और अजमेर में 17 तथा अलवर में 12 केस मौजूद हैं। वहीं 9 जिले बारां, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर कोटा, नागौर, पाली और उदयपुर में 10 से भी कम केस बचे हैं। प्रदेश में बुधवार को भी कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 8955 लोगों की मृत्यु हो

चुकी है। जयपुर में आज फुलेरा, राजापार्क व टॉक फाटक इलाके में 1-1 नया संक्रमित पाया गया है। वहीं इस बीच जयश्री स्कूल की एक और छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है। जयपुर सीएमएचओ डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि इस स्कूल में मंगलवार को डे बोर्डिंग सेंटर में रहने वाले 13 बच्चे संक्रमित मिले थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूल पहुंचकर वहां रह रहे बच्चों और स्टाफ सहित 43 लोगों के सैम्पल लिए थे। इनमें से बुधवार को एक छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव छात्रा का इलाज बोर्डिंग सेंटर में ही चल रहा है,

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ममता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सहायक ने एक ट्वीट में जोर देकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं के कथित उत्पीड़न को लेकर तथ्यों की जानकारी एवं आंकड़ों के लिए, उन्होंने ममता के साथ मीटिंग की थी। तृणमूल के टिवट हंडल ने भी ममता के साथ उनकी मीटिंग की पुष्टि कर दी है।

उनके उक्त सहायक ने कहा कि यद्यपि डॉ. स्वामी औपचारिक रूप से तृणमूल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वे ममता के पक्ष में तो जा ही चुके हैं। दरअसल, वे अपने राज्यसभा के कार्यकाल के बीच में अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी राज्यसभा सीट के बीच में अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी राज्यसभा सीट को खोना नहीं चाहते। वे

मन्तव्य होता था, की श्रेणी की राजनेता हैं। भारतीय राजनीति में यह गुण दुर्लभ है।

एक अन्य ट्वीट में, डॉ. स्वामी ने गुह मंत्री अमित शाह पर प्रहार करते हुए कहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं के करलेआम की कोई चिन्ता ही नहीं है। "आश्चर्यजनक बात है कि ए.बी. तथा जी.बी. मुझे ट्वीट कर रहे हैं- बंगाल में हिन्दुओं की हत्या क्यों?" ए.बी. तथा जी.बी. को उनसे पूछना चाहिये क्योंकि वे ही उनके संरक्षक हैं?" "ए.बी." उन "अंध भक्तों" के लिये प्रयुक्त हुआ है, जो बिना सोचे-समझे भाजपा या दक्षिण पंथ का समर्थन करते हैं तथा "जी.बी." "अंध-भक्तों" के लिये प्रयुक्त हुआ है।

और वह एसिडोमेटिक है। स्कूल में अब तक 14 बच्चे कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। फिलहाल स्कूल को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इधर दूसरी और स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बुधवार को शिक्षा संकुल में विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डॉ. कल्ला ने कहा कि प्रदेश में फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। और इसकी चपेट में स्कूलों छात्र भी आ रहे हैं। स्कूलों के मौजूदा हालातों को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम करने और अल्टरनेट डे बुलाने और ऑनलाइन क्लास का प्रस्ताव रखा गया। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही सरकार के स्तर पर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी तक निजी स्कूलों में ही कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के संक्रमित न होना अच्छी बात है। उन्होंने अभिभावकों और स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, ऐसे में सभी को भी सतर्क रहना है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी स्कूलों में कोविड वैक्सिन से लेकर अन्य सुरक्षा के बंदोबस्त किस तरह से किए जा रहे हैं और विभाग की ओर से इनकी क्या मांतिरंगी की जा रही है।

संसद के लिये ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तरह से कारवाई की जाए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कुछ सुधारों पर काम होना अभी शेष है और इसलिए बेहतर होगा, यदि प्रधानमंत्री संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से एक दिन पूर्व रविवार को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर सर्वानुमति प्राप्त कर लें। गुरुवार की मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग में अपनाई जाने वाली रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कश्मीर में बुधवार को मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये

श्रीनगर, 24 नवंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये।

- मारे गये आतंकीयों में टी.आर.एफ. का एक कमाण्डर भी शामिल है।

शामिल है। पुलिस ने बताया कि रामबाग इलाके में आज शाम एक संक्षिप्त मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये। पुलिस के एक ट्वीट में कहा, पुलिस ने श्रीनगर में तीन आतंकीयों को मार गिराया। मारे गये आतंकीयों की पहचान और वे किस संगठन से तात्त्विक रखते थे, इसका पता लगाया जा रहा है।

कृषि कानून ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गए साधन अधिक मायने रखते हैं। मित्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कृषि पर सरकार के अत्यधिक नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कृषि कानून सिर्फ इसलिए विफल नहीं हुए कि इनके उद्देश्यों को लेकर काफी वैचारिक धुंकीकरण था बल्कि ये इसलिए विफल हुए, क्योंकि जून 2020 में अध्यादेशों के जरिए नाटकीय साधन अपनाए गए और फिर सितम्बर 2020 में इन्हें संसद से पारित करवाया गया। मित्रा कहते हैं कि "कृषि सुधार" पहल की बागानी ये थी कि इसमें संसदीय प्रक्रिया की पूर्णतया उपेक्षा की गई और यह भी कि इसके प्रमुख हित धारकों से भी किसी अर्थपूर्ण संवाद या विचार-विमर्श से ठोस इंकार किया गया। मनमाने साधनों के कारण अन्ततः नीति ही धरासाई हो गई। वे कहते हैं कि सुधारों का दावा करते वक्त क्या यह अपनाए गए साधनों का गुणगान करने में हुई विफलता है और वहीं सुधारों के पूरे विचार को बदनाम कर रही है।

रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल

अदिति सिंह पहले गांधी परिवार के काफी करीब मानी जाती थीं, वे दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं

लखनऊ, 24 नवम्बर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अदिति सिंह रायबरेली से विधायक हैं, और पहले गांधी परिवार के काफी करीब मानी जाती थीं।

अदिति सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं, और जीत हासिल करके पहली बार विधानसभा पहुंची थीं। सिंह पांच बार विधायक रहे दिवंगत कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं। इनके भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के उस गढ़ में सेंध लग सकती है, जहां अभी तक भाजपा नहीं घुस पाई थी।

अदिति सिंह भले ही 2017 में कांग्रेस विधायक के रूप में विधानसभा पहुंची थीं। लेकिन कई मौकों पर वो अपनी ही पार्टी की जगहकर आलोचना करती दिखी थीं। कई बार उन्हें भाजपा

- अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सेंध लग सकती है, जहां अभी तक भाजपा नहीं घुस पाई थी।

और योगी सरकार की तारीफ और समर्थन करते हुए देखा जा चुका है। इसके साथ ही अदिति एक से अधिक मौकों पर यूपी विधानसभा में भाजपा के पक्ष में मतदान भी कर चुकी हैं। कोरोना के समय लॉकडाउन में जब कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों की व्यवस्था करने की बात कही थी और बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच गई थीं, तब अदिति सिंह ने इसकी तोखी आलोचना की थी।

इसके बाद ही अदिति सिंह को

कांग्रेस ने पार्टी की महिला विंग से निलंबित कर दिया था। हालांकि अभी तक वो पार्टी में बनी हुई थीं, लेकिन पार्टी ने एक तरह से उनसे किनारा ही कर रखा था।

अदिति सिंह से अनुग्रिया पटेल तक, यूपी में पिता की राजनीतिक विरासत जुगो बढ़ा रही है 6 नेता पिछले साल जुलाई में, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अदिति सिंह को अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस पार्टी की मांग को खारिज कर दिया था।

रायबरेली के विधायक द्वारा महामाना गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर यूपी सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष विधानसभा सत्र में भाग लेने के बाद इन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस की ओर से एक पत्र अय्यक्ष को लिखा गया था। इस सत्र का कांग्रेस ने विरोध किया था।

पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस का प्रसार करेगी ममता बनर्जी

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वार्ता)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल की तरह देश के हर राज्य में हमारी पार्टी का विस्तार करने का हमें अधिकार है और कोई भी दल हमसे संपर्क करता है तो हम वहां जाने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को यहाँ संबाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वह 30 नवम्बर को वह मुंबई में रहेंगी जहां उन्हें एक बिजनेस इवेंट में शामिल होना है। अपने मुंबई दौरे के दौरान वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के उतरने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की इकाई वहाँ शुरू हो चुकी है। मैं भी चाहती हूँ बनारस में जाऊँ और गंगा में दिया जलाऊँ और शिव मंदिर का दर्शन करूँ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश हमसे मदद चाहते हैं तो हम जरूर करेंगे। ममता बनर्जी से जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वह बोलीं, मैंने किसी से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था।

भारत में महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम हुई

पांचवे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय औसत के अनुसार पहले हर महिला औसतन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी जो घटकर 2.0 हो गई है

- चंडीगढ़ में महिला प्रजनन दर 1.4 और उत्तर प्रदेश में 2.4 है।
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में महिला प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत (2.0) से कम है।

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वार्ता)। देश में गर्भनिरोधक का प्रयोग बढ़ रहा है और महिला प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पंचम में यह दावा करते हुए कहा गया है कि देश में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। सर्वेक्षण में शामिल सभी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला प्रजनन दर 1.4 से लेकर 2.4 दर्ज की गयी है। चंडीगढ़ में महिला प्रजनन दर 1.4 और उत्तर प्रदेश में 2.4 है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में महिला प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सर्वेक्षण के अनुसार समग्र

गर्भनिरोधक प्रयोग दर (सीपीआर) अखिल भारतीय स्तर पर 54 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक बढ़ गई है। लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है। नीति आयोग के सदस्य-स्वास्थ्य डॉ वी के पाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पंचम के दूसरे चरण के अंतर्गत जनसंख्या,

परजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य पर प्रमुख संकेतकों की 'फैक्टशीट' जारी की। इस सर्वेक्षण में 14 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल किये गये हैं। पहले चरण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिसंबर, 2020 में जारी किए गए थे।

'एस.सी. एवं एस.टी. वालों के साथ आई.आई.टी. संस्थानों में भेदभाव?'

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, एस.सी. व एस.टी. के छात्रों के दाखिले एवं शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की जाती है

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में आरक्षण नियमों की बागानी ये थी कि इसमें संसदीय प्रक्रिया की पूर्णतया उपेक्षा की गई और यह भी कि इसके प्रमुख हित धारकों से भी किसी अर्थपूर्ण संवाद या विचार-विमर्श से ठोस इंकार किया गया। मनमाने साधनों के कारण अन्ततः नीति ही धरासाई हो गई। वे कहते हैं कि सुधारों का दावा करते वक्त क्या यह अपनाए गए साधनों का गुणगान करने में हुई विफलता है और वहीं सुधारों के पूरे विचार को बदनाम कर रही है।

- याचिकाकर्ता ने विभिन्न माध्यमों की खबरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि करीब 2400 विद्यार्थी जातीय आधार पर प्रताड़ित करने एवं अन्य अज्ञात कारणों से बिना डिग्री लिये आईआईटी छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं, जबकि 50 की मौत हुई है।
- संसद में 2018 पेश किये गये आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि विभिन्न आईआईटी में 6043 संकाय सदस्य हैं, जिनमें मात्र 21 एसटी और 149 एससी से हैं।

ओर से दायर याचिका में आरक्षण लागू करने में भेदभाव के अलावा प्रताड़ना और इसकी वजह से बड़ी संख्या में होनहार विद्यार्थियों के खुदकुशी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति

(एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों के संकाय सदस्यों की भर्ती और शोध विद्यार्थियों के दाखिले में कथित तौर पर कानून की अनदेखी तथा प्रताड़ना के आरोप लगाये गए हैं। याचिकाकर्ता ने विभिन्न माध्यमों की खबरों का हवाला देते हुए आरोप

लगाया है कि करीब 2400 विद्यार्थी जातीय आधार पर प्रताड़ित करने एवं अन्य अज्ञात कारणों से बिना डिग्री लिये आईआईटी छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं, जबकि 50 की मौत हुई है। आशय यह कि इस मामले में देश के इन प्रतिष्ठित संस्थाओं की ओर से कभी भी वास्तविक कारण नहीं बताये गये। संसद में 2018 पेश किये गये आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि विभिन्न आईआईटी में 6043 संकाय सदस्य हैं, जिनमें मात्र 21 एसटी और 149 एससी से हैं। याचिकाकर्ता ने संकाय सदस्यों के कामकाज के मूल्यांकन तथा तब मानकों के मुताबिक काम नहीं करने वालों को उनके पद से हटाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने का आदेश केंद्र को देने की मांग की गई है।

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय में फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार तक) पुनः लागू करने की मांग करते हुए यहां के 114 वकीलों ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति एल. एन. राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य डी. के. ठाकुर एवं अन्य की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार कर ली। शीघ्र अदालत में इस याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' एस. सिंह ने आज पीठ के समक्ष 'विशेष उल्लेख' के तहत वचौद सुनवाई की दलील छो

वाली परेशानियों एवं कानूनी पहलुओं का जिक्र करते हुए इस मामले में शीघ्र विचार करने का निवेदन किया। वकीलों ने 'ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जुरिस्ट एवं अन्य बानाम उत्तराखंड उच्च न्यायालय' मामले (रिट याचिका) में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों का कहना है कि वचौद सुनवाई के दौरान कई तरह की तकनीकी परेशानियों का सामना करने के साथ ही जूनियर वकीलों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कई अन्य तर्क दिये गए हैं। उन्होंने फिजिकल सुनवाई की मांग के समर्थन में सीपीसी-1908 की धारा 153बी और सीआरपीसी-1973 की धारा 327 का हवाला देते हुए आपराधिक एवं सिविल मामले की सुनवाई को आवश्यक बताया है।